

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास मंत्रालय से हिन्दी में अनुवाद के लिए अभी तक 113 मनुअल और 2670 फार्म प्राप्त हुए हैं। 75 मनुअलों और 2,388 फार्मों का अनुवाद किया जा चुका है और उक्त मंत्रालय को लौटाया जा चुका है। 29 मनुअलों को, जो अनुवाद के विभिन्न स्तरों पर थे, उस मंत्रालय ने बाद में वापस मंगा लिया।

(ख) फिलहाल 9 मनुअलों और 282 फार्मों का अनुवाद किया जा रहा है और उन्हें यथाशीघ्र खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास मंत्रालय को लौटा दिया जाएगा।

(ग) और (घ). भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की संहिताओं, मनुअलों और फार्मों के अनुवाद की जिम्मेदारी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की है। विभिन्न कारणवश कभी-कभी देरी हो जाती है, किन्तु अनुवाद कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए बाहरी एजेंसियों से भी कुछ अनुवाद कार्य कराने का निर्णय किया गया है।

दिल्ली के कालेजों के विद्यार्थियों में असंतोष का दूर किया जाना

6020. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री श्रोम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विशिष्ट मामले कौनसे हैं जिनके सम्बन्ध में विद्यार्थियों में असन्तोष दूर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये सामान्य रूप से और किन उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है और उन पर विचार कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या LT-706/69]

मनीपुर के पुलिस तथा जेल कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

6021. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री श्रोम प्रकाश त्यागी :
श्री एम० मेघचन्द्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के पुलिस तथा जेल कर्मचारियों को वेतनमानों का पुनरीक्षण करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जाँच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मनीपुर पुलिस के निरीक्षकों तथा सहायक उप-निरीक्षकों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के विषय में मनीपुर सरकार के प्रस्ताव की जाँच की गई थी। भारत सरकार के लिए निरीक्षकों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार करना सम्भव न हो सका। सहायक उप-निरीक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव पर अभी जाँच की जा रही है। मनीपुर के जेल कर्मचारियों के वेतनमानों में

और आगे पुनरीक्षण करने के विषय में मनीपुर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

6022. श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक हिन्दी संस्था को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि नये अनुदान समान प्रतिशतता के आधार पर नहीं दिये जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ हिन्दी संस्थाओं को अनुदान प्रतिशतता के आधार पर नहीं दिये जाते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उनको वही पुरानी योजनाओं के लिए बार-बार अनुदान दिये जाते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अनुदानों को बन्द करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विवरण जिसमें हिन्दी के प्रचार के लिए विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता की राशि के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-707/69]

(ख) और (ग). स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, अनुमोदित योजनाओं के खर्च के 75

प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है, अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी माध्यम के स्कूलों और अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के मामले में उनके घाटे को पूरा करने के लिये तदर्थ आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को तेज करने के उद्देश्य से हिन्दी में उपयुक्त साहित्य के प्रकाशन के लिए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद को शत-प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। तामिलनाडु सरकार द्वारा त्रिभाषा सूत्र समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप जो व्यक्ति स्वेच्छा से हिन्दी सीखना चाहें उन्हें हिन्दी सिखाने के लिये 200 एक-अध्यापकीय हिन्दी विद्यालयों को चलाने हेतु दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को भी एक विशेष मामले के रूप में, इस वर्ष शत-प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) से (च). स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को मुख्यतः निःशुल्क हिन्दी शिक्षण की कक्षाएं, हिन्दी विद्यालय, हिन्दी पुस्तकालय और वाचनालय हिन्दी टाइप और आशुलिपि की कक्षाएं चलाने और हिन्दी प्रचारकों के प्रशिक्षण आदि के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है, ये ऐसे कार्यकलाप हैं जिन्हें प्रत्येक वर्ष जारी रखा जाना है।

हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के लिये परीक्षा

6023. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री अर्जुन सिंह भवौरिया :

श्री अशोक लाल बेरबा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की भर्ती